



डॉ० अतुल कुमार यादव

जी-20 के आयोजन से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव

पूर्व प्रधानाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष- समाजशास्त्र विभाग, ए.के. (पी.जी.) कॉलेज, शिकोहाबाद (उ०प्र०), भारत

Received-20.12.2022, Revised-24.12.2022, Accepted-29.12.2022 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सांशः द ग्रुप ऑफ 20 (G-20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विश्व की विभिन्न देशों की सरकारों की नीतियों को तय करने एवं उन्हें आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी। बाद में 20-20 को 2007 के वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संकट के मद्देनजर राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर उचित किया गया और 2009 में इसे "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" घोषित किया गया।

जी-20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है जिसमें विभिन्न देशों को चक्रवर्ती क्रम में अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त होता है। शुरुआत में जी-20 में मुख्यतया व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया लेकिन बाद में जी-20 ने अपने एजेंडे को व्यापार जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, वि. ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध जैसे मुद्दों तक विस्तारित किया है।

कुंजीभूत शब्द- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों, नीतियों, वैश्विक आर्थिक, वित्तीय मुद्दों, भ्रष्टाचार।

सदस्य देश- जी-20 में 19 देश एवं यूरोपीय संघ सम्मिलित है। ये 19 देश इस प्रकार हैं- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के 27 देश भी इसमें सम्मिलित है।

जी-20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 85% और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ जी-20 के सदस्य देश विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अतिथि देश एवं आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन- अतिथि देश के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। जी-20 के मंच पर आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों- UN, IMF, WB, WHO, ILO, FSB और OECD की मौजूदगी तथा क्षेत्रीय संगठनों के चेयर के रूप में AU, AUDA, NEPAD और ASEAN की मौजूदगी इस संगठन की महत्ता की ओर इशारा करते हैं। संगठन की अध्यक्षता करते हुए भारत जैसे संगठनों को आमंत्रित किया है।

जी-20 की कार्यप्रणाली- जी-20 की अध्यक्षता करने वाला देश इसके उद्देश्यों को एक वर्ष तक आगे बढ़ाने के साथ ही साथ होने वाले सम्मेलन की मेजबानी करता है। जी-20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं- 1. वित्तीय ट्रैक और 2. शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि वित्तीय ट्रैक के बाद शेरपा, शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं।

जी-20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है जो नेताओं के निजी दूत होते हैं। दोनों ट्रैकों के भीतर विभिन्न विषयों से जुड़े कार्यकारी समूह होते हैं इसमें सदस्य देशों के साथ ही साथ आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अतिथि देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। किसी भी देश की अध्यक्षता के दौरान के कार्यकारी समूह नियमित रूप से मिलते हैं। शेरपा पूरे वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं जिसमें शिखर सम्मेलन के लिए तय मुद्दों पर चर्चा शामिल होती है। इस प्रकार शेरपा द्वारा जी-20 के मुख्य कार्यों का समन्वय किया जाता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे सहभागी समूह होते हैं जो सदस्य देशों के नागरिक समाज, सांसदों, थिंकटैंक, महिलाओं, युवाओं, श्रम, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करते हैं।

जी-20 के पास कोई स्थाई सचिवालय नहीं है। अध्यक्षता को तीन देशों की तिकड़ी द्वारा समर्थन दिया जाता है। इस तिकड़ी में अध्यक्षता करने वाला पिछला देश अध्यक्षता करने वाला वर्तमान देश एवं भविष्य में अध्यक्षता करने वाला देश शामिल होता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान क्रमशः इंडोनेशिया भारत और ब्राजील इस तिकड़ी में शामिल देश हैं।

जी-20 की भारत की अध्यक्षता-लोगो व थीम जी-20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों- केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को कमल के साथ जोड़ता है। यहां हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल देश के इतिहास,



संस्कृति, आध्यात्मिकता, फलदाई होने, संपदा एवं ज्ञान का प्रतीक है। इस कमल की सात पंखुड़ियां सात समुद्रों और सात महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इस कमल के साथ पृथ्वी इस बात का प्रतीक है कि भारत वैश्विक कल्याण का समर्थक है और भारत विश्व को एक परिवार मानता है। जी-20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में "भारत" लिखा है।

भारत के जी-20 की अध्यक्षता का विषय है- वसुधैव कुटुंबकम्। इस वाक्य को महाउपनिषद् से लिया गया है जो एक धरती, एक परिवार एवं एक भविष्य का है। यह थीम या विषय निश्चित रूप से जीवन के सभी रंगों एवं मूल्यों का इस धरती पर प्रतिनिधित्व करने के साथ ही साथ इस धरती को ब्रह्मांड से जोड़ने का प्रयास करता है।

थीम इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन शैली में ऐसे विकल्पों का चुनाव करना है जिससे एक अधिक स्वच्छ, अधिक हरित तथा सतत व धारणीय विकास के साझा लक्ष्यों को आने वाली पीढ़ियों के लिए साकार कर सकें क्योंकि यह धरती हमें विरासत में नहीं मिली है बल्कि यह आगे आने वाली पीढ़ियों का इस वर्तमान पीढ़ी पर उधार है। इस प्रकार यह थीम एक विकसित, समृद्ध, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सहिष्णु भारत एवं विश्व की कल्पना करती है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन जी-20 का 18वां शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली ने जा रहा है। ऊपर वर्णित सभी कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शिखर सम्मेलन के समापन पर जी-20 के नेताओं की संयुक्त घोषणा को अपनाया जाएगा। इस घोषणा में साल भर मंत्रिस्तरीय एवं कार्यकारी समूह के स्तर पर की गई चर्चाओं एवं प्राथमिकताओं के प्रति साझी प्रतिबद्धता एवं सहमति व्यक्त की जायेगी। साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए नई दिल्ली में जी-20 का अस्थायी सचिवालय बनाया गया है जिसका पता है-

सुषमा स्वराज भवन, 15-A, रिजाल मार्ग, घाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

शेरपा ट्रैक- प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और अनुशांसाए प्रस्तुत करने के लिए शेरपा ट्रैक के माध्यम से निम्नलिखित 13 कार्यकारी समूह और 2 इनिशिएटिव भारत की अध्यक्षता में मुलाकात करेंगे।

कार्यसमूह- जी-20 की निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कार्यकारी समूह, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक अनेक मुद्दों के गहन विश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकारी समूह होते हैं।

1. कृषि- वैश्विक खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए 2011 में फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी के दौरान जी-20 कृषि प्रतिनिधि समूह बनाया गया था। तब से यह यूएन 2030 के एजेंडे, विशेष रूप से जीरो हंगर (एसडीजी 2) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण षि संबंधी मुद्दों पर जी20 सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। कार्य समूह खाद्य सुरक्षा पोषण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, भोजन की बर्बादी और नुकसान, धारणीय और लचीले तथा समावेशी खाद्य मूल्य शृंखला जैसे वैश्विक मुद्दों पर सूचना विनिमय और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

2. भ्रष्टाचार निरोधक- जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह (ACWG) स्थापना 2010 में हुई थी। भ्रष्टाचार विरोध की कार्य समूह जी-20 नेताओं को भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर रिपोर्ट करता है और जी-20 देशों की कानूनी प्रणालियों के बीच न्यूनतम सामान्य मानकों को स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने हेतु यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अखंडता और पारदर्शिता, रिश्वतखोरी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संपत्ति की वसूली, लाभकारी स्वामित्व सम्बन्धी पारदर्शिता, कमजोर क्षेत्रों और क्षमता निर्माण पर केंद्रित करता है।

3. संस्कृति- जी-20 संस्कृति मंत्रियों ने 2020 में पहली बार मुलाकात की और जी-20 एजेंडे को आगे बढ़ाने में संस्कृति के सीमा पार योगदान पर प्रकाश डाला। संस्कृति और अन्य नीतिगत क्षेत्रों के बीच तालमेल का पहचानते हुए और विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों पर संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर विचार पर करते हुए, संस्कृति को 2021 में संस्कृति कार्य समूह के रूप में जी-20 एजेंडे में एकीकृत किया गया था। समूह का उद्देश्य सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग को मजबूत करना है।

4. डिजिटल अर्थव्यवस्था- 2021 में स्थापित डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप अर्थव्यवस्थाओं की डिजिटल क्षमता को दोहन करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रेरणा और व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वर्किंग ग्रुप का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने और समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए डिजिटल परिवर्तन को मूर्त रूप देना है।

5. आपदा जोखिम में कमी- जी-20 देशों में आपदा जोखिम का उच्च स्तर है, संयुक्त अनुमानित वार्षिक औसत नुकसान +218 बिलियन या बुनियादी ढांचे में उनके औसत वार्षिक निवेश का 9% है। जी20 नेताओं की घोषणाओं ने समय-समय पर जोखिम में कमी और लचीलेपन के महत्व को स्वीकार किया है। हालांकि, इस मुद्दे को जी-20 द्वारा व्यापक



और निरंतर तरीके से उठाया नहीं गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह इसलिए जी-20 द्वारा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करने, बहु-विषयक अनुसंधान करने और आपदा जोखिम में कमी पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए भारत की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है।

6. विकास- डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (DWG) 2010 में अपनी स्थापना के बाद से जी-20 'विकास एजेंडा' के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और इसके लक्ष्यों को अपनाने के बाद, वॉल ने शेरपाओं को जी-20 सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने एवं अन्य पक्षकारों के साथ काम करने हेतु सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है जिससे 2030 एजेंडे को प्राप्त करने के प्रयासों के साथ जी-20 कार्यों के सतत विकास अंतर्सम्बन्धों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

7. शिक्षा- एजुकेशन वर्किंग ग्रुप (EdWG) की स्थापना 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। स्कूल तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण, सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वित्त पोषण, शिक्षा के लिए साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूल कौशल विकास और स्कूल-टू-वर्क ट्रांजिशन जैसे अंतर्सम्बद्ध मुद्दों पर कारवाई करने के लिए रोजगार और अन्य कार्यसमूहों के साथ भी सहयोग करता है।

8. रोजगार- एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप (EWG) की शुरुआत जी-20 टास्कफोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट- 2011 में फ्रेंच प्रेसिडेंसी के तहत हुई थी -जिसे 2014 में ऑस्ट्रेलियाई प्रेसिडेंसी के तहत नेताओं की घोषणा के बाद वर्किंग ग्रुप स्तर तक बढ़ा दिया गया था। मॉल की पहली बैठक 2015 में तुर्की प्रेसिडेंसी के तहत हुई थी। EWG मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी और रोजगार-समृद्ध विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

9. पर्यावरण और जलवायु स्थिरता- क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप (CSWG) की स्थापना 2018 में अर्जेंटीना प्रेसिडेंसी के दौरान की गई थी, जबकि पर्यावरण प्रतिनिधियों की बैठक 2019 में जापान की प्रेसिडेंसी के तहत शुरू हुई थी। EDM और CSWG पर्यावरण और जलवायु सम्बन्धी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी, महासागर स्वास्थ्य, समुद्री कूड़े, प्रवाल भित्तियाँ, भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने के तरीके शामिल हैं।

10. ऊर्जा संक्रमण- सतत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में 2009 से ही जी20 में ऊर्जा पर चर्चा की गई है। ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2013 में एक समर्पित एनर्जी सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई थी। 2017 में, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में ऊर्जा पर चर्चा की गई थी। 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता के दौरान, ऊर्जा के मुद्दों को जलवायु से अलग कर दिया गया था और इन्हें एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के तहत ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा की और अग्रसर किया गया था। यह कार्य समूह ऊर्जा सुरक्षा, पहुँच और सामर्थ्य, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण पर विचार-विमर्श करता है।

11. स्वास्थ्य- महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर संवाद बढ़ाने और जी-20 नेताओं को सूचित करने के लिए 2017 में जर्मन प्रेसिडेंसी के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की स्थापना की गई थी। समूह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए समान स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध स्थायी कल्याणकारी समाज बनाने की दिशा में काम करता है। यहाँ स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी, एक स्वास्थ्य ष्टिकोण, डिजिटल स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन, सतत वित्त पोषण आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

12. व्यापार और निवेश- व्यापार और निवेश कार्य समूह (जैज) 2016 में स्थापित किया गया था। यह जी-20 व्यापार और निवेश तंत्र को मजबूत करने, वैश्विक व्यापार विकास को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने, वैश्विक निवेश नीति सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने तथा समावेशी व समन्वित वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने सहित अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है।

13. पर्यटन- 2020 में अपनी स्थापना के बाद से, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप द्वारा सदस्य देशों और प्रासंगिक हितधारकों को स्थानीय और वैश्विक पर्यटन के आगे के विकास के लिए चर्चा विचार-विमर्श और मार्गदर्शन करने के लिए एक साथ लाया गया है, साथ ही ब्रूटप - 19 महामारी सहित इन क्षेत्र के सामने आने वाली आम चुनौतियों को भी कम किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसकी प्रगति को देखते हुए, पर्यटन को अधिक टिकाऊ बनाना और इसके लचीलेपन को बढ़ाना हाल के दिनों में इस कार्य समूह का प्रमुख विषय रहा है।

भारत में शेरपा ट्रैक के तहत अब तक कार्यक्रम-

1. पहली शेरपा बैठक, 04 से 07 दिसंबर 2022, स्थान-उदयपुर।



2. पहली विकास कार्य समूह की बैठक, 13 से 16 दिसम्बर 2022 स्थान-मुंबई।
3. पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, 18 से 20 जनवरी, स्थान- तिरुवनंतपुरम।
4. पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक, 31 जनवरी से 02 फरवरी, स्थान-चेन्नई।
5. पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक, 02 से 05 फरवरी, स्थान-जोधपुर।
6. पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 05 से 07 फरवरी, स्थान-बेंगलुरु।
7. पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक 09 से 11 फरवरी, स्थान- बेंगलुरु।
8. पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक, 07 से 09 फरवरी, स्थान- कच्छ का रन।
9. पहली .षि कार्य समूह की बैठक, 13 से 15 फरवरी, स्थान-इंदौर।
10. पहली डिजिटल इकोनामी कार्य समूह की बैठक, 13 से 15 फरवरी, स्थान-लखनऊ।
11. पहली संसृति कार्य समूह की बैठक 23 से 25 फरवरी, स्थान-खजुराहो।
12. पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक, 01 से 04 मार्च, स्थान-गुरुग्राम।
13. दूसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक, 15 से 17 मार्च, स्थान-अमृतसर।
14. दूसरी पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक, 27 से 29 मार्च, स्थान- गांधीनगर।
15. पहली निवेश व कार्य समूह की बैठक, 28 से 30, स्थान-मुंबई।
16. दूसरी .षि कार्य समूह की बैठक, 29 से 31 मार्च, स्थान-चंडीगढ़।
17. दूसरी शेरपा बैठक, 30 मार्च से 02 अप्रैल, स्थान-कुमारकोम।
18. पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक 30 मार्च से 01 अप्रैल, स्थान- गांधीनगर।
19. दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक, 03 से 05 अप्रैल, स्थान-गुवाहाटी।
20. दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक, 03 से 05 अप्रैल, स्थान-सिलीगुड़ी/दार्जिलिंग।
21. दूसरी विकास कार्य समूह की बैठक, 06 से 09 अप्रैल, स्थान- कुमारकोम।
22. दूसरी डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक, 17 से 19 अप्रैल, स्थान- हैदराबाद।
23. दूसरी स्वास्थ्य का समूह की बैठक, 17 से 19 अप्रैल, स्थान- गोवा।
24. कृषि क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक, 17 से 19 अप्रैल, स्थान- वाराणसी।
25. तीसरी शिक्षा कार्यक्रमों की बैठक, 24 से 27 अप्रैल, स्थान- भुवनेश्वर।

वित्तीय टैक- जी-20 वित्त टैक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवतरी उनके प्रतिनिधियों और विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। वित्त टैक द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं- वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और वैश्विक आर्थिक जोखिमों की निगरानी, अधिक स्थिर और लचीले वैश्विक वित्तीय में सुधार, अंतरराष्ट्रीय कराधान, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का वित्तपोषण, स्थायी वित्त, वित्तीय समावेशन, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वित्तपोषण और महामारी की रोकथाम, निपटने की तैयारी तैयारी और प्रतिक्रिया में निवेश। विशेष रूप से महामारी के बाद के चरण में वित्त टैक की कुछ प्रमुख उपलब्धियां ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI), DSSI से परे ऋण उपचार के लिए सामान्य ढांचा, जी-20 सरस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप, के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का द्विपक्षीय समाधान। गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश के लिए जी-20 सिद्धांत, महामारी च्त् आदि के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि (FIF) बनाने का प्रस्ताव आदि हैं।

कार्य समूह-

1. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप- फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (FWG) वर्तमान प्रासंगिकता के वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक मुद्दों, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी, और जी-20 भर में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास (टप्ल) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय के संभावित क्षेत्र में चर्चा करता है। भारत और यूके इस कार्यकारी समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचा- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (IFA) कार्यकारी तन्ह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना से संबंधित मुद्दों का निपटारा करता है जैसे- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (GESN) विकास वित्त से संबंधित मामले, ऋण कमजोरियों का प्रबंधन और ऋण पारदर्शिता बढ़ाना; पूंजी प्रवाह प्रबंधन और स्थानीय मुद्रा बांड बाजारों को बढ़ावा देना। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता दक्षिण कोरिया और फ्रांस द्वारा की जाती हैं।

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर किंग ग्रुप- इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG) इन्फ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श



करता है जिसमें शामिल हैं— एक एसेट क्लास के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना शामिल है; गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेश को बढ़ावा देनाय इन्फ्रास्ट्रक्चर; और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अभिनव उपकरणों की पहचान करना। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील द्वारा की जाती है।

5. सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप— सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (SFWG) 2021 जी-20 इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत अमेरिका और चीन की सह-अध्यक्षता वाला एक नया स्थापित समूह है। कार्यकारी समूह इस बात पर विचार करता है कि जी-20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व अन्य हितधारकों का ध्यान स्थायी वित्त एजेंडों की प्रमुख प्राथमिकताओं पर कैसे केंद्रित किया जाए और की जाने वाली प्रमुख कार्रवाइयों पर आम सहमति बनाई जाए।

6. वित्तीय समावेशन के लिए टेक्स्ट आगीदारी— वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विश्व तर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसके कार्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली के बुनियादी में सुधार के तरीके, उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अनुकूल नीतियों का प्रेषण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना और प्रेषण हस्तांतरण की लागत को कम करना, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और दूसरों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करना शामिल है। GPF1 की सह-अध्यक्षता इटली और रूस द्वारा की जाती है।

7. संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल— संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स की स्थापना जी-20 रोम लीडर्स समिट, 2021 के दौरान की गई थी। टास्क फोर्स का उद्देश्य है— महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पीपीआर से सम्बन्धित मुद्दों पर संवाद और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय व्यवस्था विकसित करना, सामूहिक आर्वाइ को बढ़ावा देना, सीमा पार प्रभाव के साथ स्वास्थ्य आपात स्थितियों का आकलन करना और उन्हें समाधान करना, और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाते हुए महामारी पीपीआर के लिए संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

8. अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडा— जी-20 वित्त ट्रैक में अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडे पर सीधे जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा की जाती है और जी-20 के तत्वावधान में पर कोई औपचारिक कार्य समूह नहीं है। समूह के तहत चर्चा किए गए मामलों में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों को संबोधित करना, कर चोरी के खिलाफ लड़ाई, बैंक गोपनीयता और टैक्स हेवन को समाप्त करना, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर से बचाव को संबोधित करना शामिल है। जी-20 अंतरराष्ट्रीय कर एजेंडे पर काम ँब के समावेशी ढांचे में किया जाता है।

9. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे— जी-20 वित्त ट्रैक में, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों के स्तर पर सीधे चर्चा की जाती है। जी-20 वित्त ट्रैक के तत्वावधान में वित्तीय क्षेत्र मुद्दों पर कोई औपचारिक कार्य समूह नहीं है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड जी-20 वित्तीय क्षेत्र के एजेंडे पर प्रतिभागियों की चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक चर्चा पत्र उपलब्ध करवाता है। वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के तहत चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करना, विवेकपूर्ण निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन में सुधार, पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना, सीमा पार भुगतान को बढ़ाना, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) और जलवायु संबंधी वित्तीय मामलों में संरचनात्मक कमजोरियों का समाधान शामिल हैं। जोखिम, क्रिप्ट परिसंपत्तियों से जोखिमों का आकलन और दूसरों के बीच नीतिगत दृष्टिकोण की व्यावहारिकता पर विचार करना भी शामिल हैं।

भारत की अध्यक्षता में वित्त ट्रैक के अंतर्गत अब तक निर्धारित कार्यक्रम—

भारत की अध्यक्षता में वित्त ट्रैक के अंतर्गत निर्धारित अब तक इस प्रकार हैं—

1. पहली वित्त व सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग, 13 से 15 दिसंबर 2022 स्थान— बेंगलुरु।
2. पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 16 से 17 दिसंबर, स्थान—बंगलुरु।
3. पहली संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्यबल की बैठक, 20 दिसंबर (वर्चुअल मोड)।
4. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए पहली बैठक 09 से 11 जनवरी, स्थान— कोलकाता।
5. पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 16 से 17 जनवरी स्थान— पुणे।
6. पहली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यसमूह बैठक 30 से 31 जनवरी स्थान— चंडीगढ़।
7. पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 02 से 04 फरवरी स्थान गुवाहाटी।
8. पहली एफएमसीबीजी और दूसरी एफसीबीडी बैठक 22 से 25 फरवरी, स्थान— बेंगलुरु।
9. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए दूसरी बैठक 06 से 07 मार्च, स्थान— हैदराबाद।



0. दूसरी संयुक्त वित्त स्वास्थ्य टास्क फोर्स बैठक. 20 मार्च (वसुंल नोड)।
11. दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 21 से 23 मार्च स्थान- उदयपुर।
12. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, 24 से 25 मार्च स्थान- चेन्नई।
13. दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, 28 से 29 मार्च, स्थान- विशाखापट्टनम।
14. दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक, 30 से 31 मार्च, स्थान- पेरिस।
15. दूसरी वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक. -2 से 13 अप्रैल, स्थान वाशिंगटन डीसी।

'शेरपा ट्रैक और वित्त ट्रैक की अब तक की उपर्युक्त बैठकों के अतिरिक्त जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 01 से 02 मार्च नई दिल्ली में प्रस्तावित है।

शेरपा ट्रैक, वित्तीय ट्रैक और सहभागी समूह के कार्यक्रमों की मेजबानी करने वाले शहरों के नाम इस प्रकार हैं- अमृतसर, बेंगलुरु, भुनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई दिल्ली, गांधीनगर, गोवा, गुरुग्राम, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, कोच्चि, कोलकाता, कुमारकोम, लखनऊ मुंबई, पुणे, कच्छ, शिलांग, सिलीगुडी, सूरत, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर, वाराणसी और विशाखापट्टनम। सहभागी समूह (एंगेजमेंट ग्रुप)

एंगेजमेंट ग्रुप में प्रत्येक जी-20 सदस्य देशों के गैर-सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं और जी-20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार नीति-निर्माण प्रक्रिया में वे अपना योगदान देते हैं। सहभागी समूहों के तहत निम्नलिखित समूह आते हैं-

1. व्यापार 20- द बिजनेस 20 (बी20) वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक जी20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित बी-20, जी-20 में सबसे प्रमुख सहभागी समूहों में से एक है। जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं। बी-20 वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं के वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन के मुद्दों पर विचारों को उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और पूरे जी-20 व्यापार समुदाय के लिए एक स्वर में बोलता है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (BIF) को भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के लिए बिजनेस 20 (बी-20) सचिवालय के रूप में नामित किया गया है। बी-20 इंडिया पूरे भारत में चर्चाओं और नीति समर्थन मंचों की एक शृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें पहचानी गई उद्योग प्राथमिकताओं को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बी-20 रणनीतिक ष्टि को साकार करना और इसे ठोस और कार्रवाई योग्य नीतिगत सिफारिशों में बदलना है।

2. सिविल 20- सिविल20 (सी-20) सहभागी ग्रुप को 2013 में एक आधिकारिक जी-20 सहभागी ग्रुप के रूप में लॉन्च किया गया था, हालांकि जी-20 सदस्य देशों के बीच सिविल सोसाइटी की सहभागिता 2010 में शुरू हो गयी थी। सी-20 गैर-सरकारी और गैर-व्यवसायिक पक्ष की आवाज को जी-20 के समक्ष लाने के लिए पूरे विश्व के सिविल सोसाइटी संगठनों को एक मंच प्रदान करता है। यह वह स्थान उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से वैश्विक सिविल सोसाइटी संगठन जी-20 में व्यवस्थित और स्थाई रूप से योगदान कर सकते हैं।

3. मजदूर 20- मजदूर-20 (एल-20) शिखर सम्मेलन पहली बार औपचारिक रूप से 2011 में फ्रेंच प्रेसीडेंसी के दौरान हुआ था। एल-20, जी-20 देशों के ट्रेड यूनियन नेताओं को बुलाता है और श्रम संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

4. सांसद 20- पार्लियामेंट20 (पी-20) सहभागी ग्रुप, 2010 में कनाडा की अध्यक्षता के दौरान शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व जी-20 देशों की संसदों के स्पीकर करते हैं। चूंकि सांसद संबंधित सरकारों का मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः पी-20 बैठकों का उद्देश्य वैश्विक शासन में एक संसदीय आयाम लाना, जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रभावी रूप से राष्ट्रीय वास्तविकताओं में रूपांतरित हों।

5. विज्ञान 20- विज्ञान- 20 सहभागी ग्रुप, जिसमें जी-20 देशों की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियां शामिल हैं, को 2017 में जर्मनी की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया था। यह नीति निर्माताओं हेतु आम सहमति-आधारित विज्ञान-संचालित अनुशांसा प्रस्तुत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले कार्यबलों के माध्यम से तैयार की जाती हैं।

6. साई 20- सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स 20 (IF20) 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी द्वारा शुरू किया गया एक सहभागी ग्रुप है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और जी-20 सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में वैश्विक स्तर पर SAI द्वारा निमाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने का एक मंच है।

7. स्टार्टअप 20- स्टार्टअप 20 सहभागी ग्रुप की शुरुआत 2023 के जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत की जा रही है,



जो स्टार्टअप को समर्थन देने और स्टार्टअप, कॉरपोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल को संक्षम बनाने के लिए एक वैश्विक संस्था बनाने की इच्छा रखता है।

इस समूह का उद्देश्य जी20 सदस्य देशों के स्टार्टअप को एक साथ आने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है ताकि सक्षम क्षमता के निर्माण, फंडिंग गैप की पहचान, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति और जलवायु नवाचारों हेतु रोड मैप विकसित किया जा सके और एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जा सके।

8. सोचो-20 (थिंक-20)— थिंक-20 (टी-20), एक आधिकारिक जी-20 सहभागी ग्रुप के रूप में, 2012 में मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। यह प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थिंक टैंक और उच्च-स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर जी-20 के लिए एक "विचार बैंक" के रूप में कार्य करता है ताकि टी-20 अनुशासकों को नीतियों के रूप में विकसित किया जा सके और इसे जी-20 कार्यकारी समूहों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है जिससे जी-20 को ठोस नीतिगत उपाय प्रस्तुत करने में मदद मिल सके।

9. शहरी 20— अर्बन 20 या यू-20 एक सिटी डिप्लोमेसी पहल है, जिसमें जी-20 देशों के शहर शामिल हैं। यह एक सामूहिक संदेश विकसित करने के लिए शहरों के बीच जुड़ाव की एक स्थायी प्रथा स्थापित करने का प्रयास करता है जो सतत विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में शहरों की भूमिका पर जोर देता है। यू-20 सहभागी समूह समग्र जी-20 वार्ताओं को सूचित करने और समृद्ध करने के लिए शहरों से शिष्टाचार, चिंताओं और विचारों के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यू-20 को 2017 में ब्यूनस आयर्स और पेरिस के मेयरों के नेतृत्व में शहरों की विशिष्ट चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, यू-20 शहरों के प्रतिनिधियों और नेताओं को एक साथ लाने के लिए स्थापित किया गया था। सी-40 और UCLG इसकी स्थापना के बाद से यू-20 के संयोजक हैं। ब्यूनस आयर्स, टोक्यो, रियाद, रोम और जकार्ता पहले यू-20 की अध्यक्षता कर चुके हैं।

अहमदाबाद, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते महानगरीय शहरों में से एक है जो यू-20 के 6वें संस्करण का अध्यक्ष है। भारत की 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन यूजर' की जी-20 थीम के अनुरूप, यू-20 अहमदाबाद इस बात पर जोर देगा कि शहर के स्तर पर कार्रवाई से स्थायी सकारात्मक वैश्विक परिणाम निकल सकते हैं, जो दुनिया और हमारे साझा भविष्य को तैयार करता है। शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान, अहमदाबाद शहर के साथ यू-20 के लिए तकनीकी सचिवालय के रूप में काम करेगा।

पिछले यू-20 विज्ञप्तियों की विरासत का निर्माण करते हुए निम्नलिखित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान वैश्विक एजेंडा का जवाब देने के लिए, शहर स्तर की कार्रवाइयों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में की गई है। इन्हें यू-20 शहरों के बीच सहयोगात्मक विचार-विमर्श द्वारा और विकसित किया जाएगा।

1. पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना।
2. जल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. जलवायु वित्त में तेजी लाना।
4. चौपियनिंग 'स्थानीय' पहचान।
5. शहरी प्रशासन और योजना के लिए ढांचे को फिर से खोजना।
6. डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना।

10. महिला 20— वीमेन-20 एक सहभागी ग्रुप है जिसे 2015 में तुर्की प्रेसीडेंसी के दौरान लॉन्च किया गया था। W20 का प्राथमिक उद्देश्य 2014 में ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में अपनाई गई "25x25" प्रतिबद्धता को लागू करना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अंतर को 25% तक कम करना है। W20 'लिंग समावेशी आर्थिक विकास' पर केंद्रित है और W20 के लिए निम्नलिखित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: जमीनी नेतृत्व, उद्यमिता, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन।

11. युवा 20— यूथ-20 (वाई-20), 2010 में आयोजित अपने पहले वाई-20 सम्मेलन के साथ एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो युवाओं को जी20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचारों को व्यक्त करने की अनुमति देता है और अनेक सिफारिशों को सामने लाता है जो जी-20 देशों के नेताओं को प्रस्तुत की जाती हैं।

जी-20 के सफल आयोजन से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव— भारत एक ऐसे समय में जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है जब दुनिया कई संकटों से गुजर रही है जैसे— कोविड महामारी के बाद का चुनौतीपूर्ण समय, यूक्रेन में चल रहे युद्ध, बहुपक्षीयतावाद का संकट, विश्व के कई देशों में मंदी की आशंका, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा कठोर आर्थिक



संरक्षणवाद की तरफ पलायन, वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई आदि बातों की चर्चा की जा सकती है। ऐसे में जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करती है। भारत के लिए यह एक ऐसा समय भी है जब वह अपनी शक्ति एवं प्रभाव तथा विश्वसनीयता का परीक्षण भी कर सकता है।

जी-20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के समक्ष उपस्थित होने वाली कुछ चुनौतियों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है—भारत के समक्ष पहली चुनौती यह है कि किस प्रकार जी-20 की विश्वसनीयता एवं साख को बनाए रखा जाए। दूसरी प्रमुख चुनौती है कि कैसे जी-20 जैसे संगठनों को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए। तीसरी चुनौती यह है कि भारत किस प्रकार से तीसरी दुनिया एवं विकासशील देशों का इस प्लेटफार्म पर नेतृत्व करें। अगली चुनौती उत्तर दक्षिण संवाद एवं दक्षिण-दक्षिण सहयोग को ज्यादा प्रभावी बनाने की है। साथ ही साथ जी-20 में यूरोपीय देशों व अनेरिका के प्रभाव को कम करते हुए कैसे इसे अन्य देशों के लिए खोला जाए यह एक अन्य विकट समस्या है। इसके अतिरिक्त अन्य चुनौतियां भी हैं।

अब यदि जी-20 की अध्यक्षता से उत्पन्न भारत के लिए अवसरों की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि यदि भारत जी-20 के देशों से कृषि क्षेत्र हेतु तकनीकी, फंड एवं प्रशासन संबंधी विशेषज्ञता हेतु सहयोग व सहमति प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो भारत अपनी कृषि क्षेत्र की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकेगा और इससे भारतीय किसानों की आमदनी बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही साथ ही साथ भारत वैश्विक मानकों के हिसाब से कृषि उत्पादक में सक्षम हो सकेगा। भारत इस सम्मेलन के माध्यम से निपटने हेतु आवश्यक कदमों की जानकारी प्राप्त करने एवं इच्छाशक्ति के निर्माण में भी एक आगे बढ़ सकेगा।

जी-20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों के मध्य सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने में इस सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। यह सम्मेलन भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के उपकरणों को और अधिक अच्छे ढंग से इस्तेमाल करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करते हुए अर्थव्यवस्था को त्वरित बनाया जा सकेगा और भ्रष्टाचार से निपटने में सहूलियत मिल सकेगी। साथ ही साथ भारत इस सम्मेलन के माध्यम से आपदा जोखिमों से निपटने में ज्यादा सक्षम हो सकेगा। इसके सफल आयोजन से भारत को धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी।

इस सम्मेलन के माध्यम से भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों एवं जरूरतों के हिसाब से उच्चतर करने में सक्षम हो सकेगा तथा भारत अपने अनुसंधान एवं विकास के साझा आयामों को बल प्रदान कर सकेगा लेकिन भारत ऐसा करने में तभी सक्षम हो सकेगा जब वह अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी जैसे अपराधों से अपने शिक्षण संस्थानों व अकादमिक जगत को बचा पाएगा।

भारत का वैश्वीकरण के दौर में होने वाला विकास रोजगारविहीन विकास के रूप में देश के समक्ष बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। ऐसे में इस सम्मेलन में होने वाली विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से भारत बेरोजगारी एवं असंतोष से निपटने हेतु नए आयामों और उपायों की ओर अग्रसर हो सकेगा। साथ ही साथ इस सम्मेलन के माध्यम से भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अपने आम जनमानस को अधिक जागरूक एवं जवाबदेह बनाने में सक्षम हो सकेगा। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत ऊर्जा क्षेत्र के नवाचारों हेतु अधिक उपाय अपनाने की स्थिति में होगा जिससे पर्यावरण अवक्रमण से निपटने में आसानी होगी।

इस सम्मेलन के स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों एवं तकनीकी सक्षम देशों के सहयोग से भारत अपने मेडिकल क्षेत्र को भविष्य में और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने की स्थिति में होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत अपने लिए अधिक निवेश और व्यापार सहूलियतें प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है बशर्ते कि वह अपने कूटनीति उपकरणों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करे। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है क्योंकि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन भारत अब तक अपनी क्षमता का एक चौथाई भी पर्यटन क्षेत्र में हासिल नहीं कर सका है। साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र भारत के लिए रोजगार के नए अवसर की खोलता है अतः भारत को इस क्षेत्र में अधिक कुशलता के साथ कार्य करना ही होगा।

वित्तीय ट्रैक के अंतर्गत होने वाली चर्चाओं के माध्यम से भारत भविष्य में होने वाले सामाजिक-आर्थिक बदलावों हेतु और अधिक अच्छे तरीके से खुद को तैयार कर सकेगा। भारत ँळए ष.।ए ँळए ँळए ँळए संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल, अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडे एवं वित्तीय क्षेत्र के स्तर पर होने वाली चर्चाओं के माध्यम से अपने लिए व तीसरी दुनिया के देशों के लिए अधिक सक्षम, धारणीय, डिजिटल तथा भरोसेमंद वैश्विक आर्थिक ढांचे के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो सकेगा।



सहभागी समूह के स्तर पर होने वाली चर्चाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से भारत व्यापार हेतु सहूलियतें तो हासिल ही कर सकता है परंतु साथ ही साथ सिविल सोसाइटी तथा मजदूरों के हितों व लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक प्रभावी बना सकेगा। भारत साई-20, स्टार्टअप-20, थिंक-20, U-20, W-20, Y-20 के माध्यम से ऑडिट, स्टार्टअप, अकादमिक व शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में नवीन उपलब्धियां हासिल करने के साथ ही साथ महिलाओं एवं युवाओं के लिए एक अधिक समृद्ध एवं सक्षम तथा संवेदनशील और अधिक सहिष्णु समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकेगा।

लेकिन बहुसंख्यकवाद, लोकप्रियतावाद, मीडिया-पाबंदी, भयादोहन एवं तानाशाही तथा क्रोनी-कैपिटलिज्म की ओर बढ़ते और अलोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने वाले भारत के लिए अपनी क्षमताओं के पूर्ण उपयोग की संभावना आज के परिवेश में संदिग्ध नजर आती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://icrier.org/g20-research/>
2. The Evolving Role of the G20 Gordon Smith Series: Perspectives on the G20: The Los Cabos Summit May 17, 2012
3. <https://www.g20.org/en/>
4. <https://g20.mygov.in/>
5. <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/g20-august-2012.pdf>
6. <https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/development/g-20-working-countries-india-position-every-details-lucknow-uttar-pradesh-summit-2023/articleshow/97860640.cms>
7. W20 (Women 20) for India's G20 Presidency
8. Aurangabad to host W20 Inception Meeting on February 27th -28th, 2023 Posted On: 25 FEB 2023 5:45PM by PIB Mumbai
9. Y20@G20 : Youth, The Forerunner of New India, BySamir Kumar
10. [https://pib.gov.in/PressReleasframePage.aspx?PRID=1885167#:~:text=Urban%2D20%20\(U20,by%20PIB%20Delhi](https://pib.gov.in/PressReleasframePage.aspx?PRID=1885167#:~:text=Urban%2D20%20(U20,by%20PIB%20Delhi)
11. <https://t20ind.org/>
